राजनीतिक तिलिस्मों पर फतह का महायज्ञ

जासूस बादशाह

www.picmp.com

आरएनआई निबंधन संख्या-एमपीएचआईएन /1999 /4107

डाक पंजीयन-मप्र /भोपाल /371 /18-20

वर्ष-19, अंक-4 (चौबीस सालों से प्रकाशित) भोपाल, रविवार 28 जनवरी 2018 पेज-8,मूल्य पांच रुपया

सरकारी योजनाओं का लक्ष्य पूरा करने में हिचकें नहीं-योगेन्द्र सिंह

भोपाल,(पीआईसीएमपीडॉटकॉम)। यूनियन बैंक के मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्र के महाप्रबंधक योगेन्द्र सिंह ने कहा है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक होने के नाते हमारी जिममेदारी है कि हम सरकार की योजनाओं को पूरा करें। सरकार की मंशा के अनुरूप देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करें। इसके बावजूद बैंकों के जन धन की रक्षा करना भी हमारा दायित्व है। इसके लिए हमें सतत निगरानी करके उन हितग्राहियों को कर्ज देना चाहिए जो वक्त पर पूंजी लौटाएं और उस पूंजी से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचा सकें। यूनियन बैंक आफिसर्स ऐसोसिएशन की क्रेडिट वर्कशाप और स्टाफ मीटिंग में उन्होंने मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के साथ अधिकारियों को ये सलाह दी।

यूनियन बैंक के उप महाप्रबंधक गुरतेज सिंह,यूनियन बैंक आफिसर्स यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभात सकसेना, छत्तीसगढ़ यूनियन बैंक आफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव अभय कुमार सिन्हा, यूनियन बैंक आफिसर्स ऐसोसिएशन रीवा के उपाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार, ने भी इस कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए। बैंक से हाल ही में सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक विपिन शर्मा को इस अवसर पर यूनियन की ओर से शाल श्रीफल भेंटकर उनका अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर श्री शर्मा ने अपनी कविता के माध्यम से बैंक और उसके अधिकारियों कर्मचारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। नई पीढ़ी के युवाओं को उन्होंने शुभाशीष भी दिया।

यूनियन बैंक के महाप्रबंधक योगेन्द्र सिंह ने कहा कि बैंक की निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए हम लोग तबादले और पोस्टिंग के माध्यम से योग्य अधिकारियों को विभिन्न स्थानों पर पदस्थ करते हैं। इसलिए उन्हें सकारात्मक नजरिए से ही लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन बैंकों ने सशक्त लीडरशिप विकसित नहीं की वे धीरे धीरे डूब गए। यूनियन बैंक में अपने कर्मचारियों की सुविधा का ध्यान सबसे पहले रखा जाता है लेकिन उनकी योग्यता को पूरी तरह फलित होने का अवसर भी मिले इसका भी ध्यान रखा जाता है। उन्होंने कहा कि यदि हम अपने अधिकारियों कर्मचारियों से नतीजों की उममीद करेंगे तो हमें उनकी योग्यता के साथ साथ उनकी पसंद का भी ध्यान रखना पड़ता है।

श्री सिंह ने कहा कि आज देश के लोग बैंकिंग के साथ साथ मयूचुअल फंडों और अन्य संसाधनों में भी रुचि दिखा रहे हैं। इसलिए हमें अपने उपभोक्ताओं को अच्छे प्रोडकट उपलबध करवाकर उनकी आर्थिक अपेक्षाओं को पूरा करना होगा। दस रुपए के सिक्के और नोटों की भरमार की समस्या पर उन्होंने कहा कि बैंकों को रिजर्व बैंक की गाईडलाईन के आधार पर सरकारी करेंसी स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र के बैंक होने के नाते हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम सरकारी अधिकारियों से निरंतर संवाद बनाकर रखें ताकि जनता की जरूरतों को पूरा करने में हम उपयोगी साबित हों।

उन्होंने बैंकों की तरफ से दिए जाने वाले सरकारी ऋणों की गुणवत्ता सुधारने के लिए अधिकारियों को एक फार्मूला दिया। जिसमें हितग्राही की योग्यता, क्षमता, उसके कारोबार के मुनाफे, के साथ साथ उस लोन को दिए जाने शर्तों के सख्ती से पालन की सलाह दी। बैंकों के ऋण ज्यादा उपयोगी बनें इसके लिए उन्होंने अपने अग्रजों और सहयोगियों से निरंतर सलाह लेने और पूर्व के अनुभवों से सीख लेने का मार्ग भी सुझाया।

बैंक के उपमहाप्रबंधक गुरतेज सिंह ने कहा कि वे कई राज्यों में काम कर चुके हैं। मध्यप्रदेश की बैंक आफिसर्स यूनियन जिस तरह सफल संवाद स्थापित करके बैंक को सफल बनाने में जुटी है वैसी दक्षता अन्य राज्यों में नहीं है।

(शेष भाग पेज सात पर पढ़िए)

Happy Independence Day

Regd No.4964

All India Union Bank Officers Federation

(Affiliated To A.I.B.O.C.)

H.Q.:26/28-D,Connaught Place,New Delhi-110001

www.aiubof.in

A.R.WANI
President

PRABHAT SAXENA
Gen.Secretary
(M) 09039033363

जनसम्पर्क

भोपाल, रविवार 28 जनवरी 2018

इस गणतंत्र की जड़ता कौन तोड़ेगा

आज से अड़सठ साल पहले भारत ने अपना संविधान लिखा और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्रात्मक राज्य की अवधारणा को फलीभूत किया था। तब ये लगा था कि आजाद हिंदुस्तान तमाम सुधारों के साथ जन जन की आकांक्षाओं को पूरा कर सकेगा।इस दिशा में बहुत सारे प्रयास भी हुए। उनमें सफलता भी मिली। इसके बावजूद आज तक इस लोकतंत्र को वैश्विक कसौटियों पर खरा नहीं साबित किया जा सका है। इसकी सबसे बड़ी वजह थी समानांतर अर्थव्यवस्था। अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के बाद जो अंग्रेजपरस्त कांग्रेसी सरकारें आईं उन्होंने चोरी की अर्थव्यवस्था को ही बढ़ावा दिया। इसकी वजह उनकी वे अनैतिक संधियां थीं जो उन्होंने अंग्रेजों को खुश करने और कथित आजादी की जल्दबाजी में कीं थीं। इन संधियों में सबसे बड़ी भूमिका पं. जवाहर लाल नेहरू और उनके वकीलों के गिरोह ने निभाई थी। ये गिरोह सत्ता पाने की इतनी हड़बड़ी में था कि उसने पाकिस्तान विभाजन भी स्वीकार किया और जम्मू कश्मीर जैसे तमाम विवादों को भी अनसुलझा बनाए रखा। देश आज तक उन नासूरों को झेल रहा है। सत्ता हस्तांतरण के दस्तावेजों में जो शर्तें लिखीं गईं उनमें देश के आर्थिक संसाधनों पर ब्रिटेन का कब्जा बरकरार था। टाटा बिड़ला जैसी भारतीय कंपनियों में निवेश करके अंग्रेजों ने अपनी आय का स्रोत बनाए रखा। आगे चलकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसलिए किया गया ताकि यहां से कर्ज लेकर डूबत खातों की राशि बटोरकर लोग ब्रिटेन में जाकर बस सकें। ब्रिटिश पार्क आज भारत में समृद्धि की मिसाल माना जाता है जबकि वो यहां का धन लूटने वालों की बस्ती है। गणतंत्र के नाम पर अंग्रेजों से की गईं संधियों के संरक्षण का काम भी बखूबी किया गया। लोकतंत्र के नाम पर कांग्रेसियों ने अपने चपरासियों, हरवाहों को लोकतंत्र के शीर्ष पर बिठा दिया। बरसों तक देश यही छल झेलता रहा। जिसने चूं चपट की उसकी फाईल न्यायपालिका में बैठे अंकल जजों ने निपटा दी। लूट का कारोबार कार्यपालिका संभालती रही। आजादी के साढ़े छह दशक बीत जाने के बाद अब पहली बार महसूस हो रहा है कि देश एक नई दिशा में अग्रसर हो रहा है। वैसे तो आर्थिक सुधारों पर पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हाराव की सरकार ने जो इबारत लिखी वो मील का पत्थर थी। इसके बावजूद कांग्रेसियों ने पच्चीस सालों तक उन सुधारों को लागू नहीं होने दिया। दस सालों तक प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहनसिंह ने कई मूलभूत सुधारों को लागू किया लेकिन समानांतर अर्थव्यवस्था के खिलाड़ियों ने उनकी सरकार को घोटालों की सरकार बना दिया। सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी लगातार धमकियां दी जा रहीं हैं। नोटबंदी और जीएसटी से हलाकान वे तमाम चोर व्यापारी भी आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को गरिया रहे हैं जिनकी चोरी की आदत अब उन्हें झमेले में डाल रही है। ऐसे चोर कांग्रेस में खूब फले फूले अब वे भाजपा में भी प्रमुख बने हुए हैं। आर्थिक सुधारों ने उनकी भी जान सांसत में फंसा रखी है। नोटबंदी यदि आपदा थी तो आरएसएस को उन तमाम आपदाओं के समान सेवा कार्य की तरह आर्थिक विकास की दिशा का मार्गदर्शन करना था। लेकिन समस्या ये थी कि आरएसएस के पास भी ऐसे स्वयंसेवक नहीं थे जो नए आर्थिक माहौल को समझ सकते और उसके अनुकूल मार्गदर्शन करते। यही वजह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद देश की आय और रुपये की समृद्धि नहीं बढ़ पा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सत्ता संभालते वक्त कहा था कि वे देश के तमाम गैर उपयोगी कानूनों को हटा देना चाहते हैं। उनके कहने के बावजूद देश में वे तमाम कानून आज तक लागू हैं जिनके माध्यम से भारत की जड़ता को संरक्षित किया जाता रहा है। नियंत्रित अर्थव्यवस्था के दौर में बने तमाम कानून आज अप्रासंगिक हो चले हैं। देश मुक्त बाजार और उपभोक्तावादी अर्थव्यवस्था की पटरी पर दौड़ रहा है। ऐसे में भारत को नए कानूनों की जरूरत है। नए विचारस्रोतों की जरूरत है। इसलिए अड़सठवें गणतंत्र के अवसर पर सबसे जरूरी प्रयास उन तमाम कानूनों को बदल डालने की है जो भारतीय गणतंत्र के पैरों की बेड़ियां बन गए हैं। अरबों के कर्ज पर सांसें ले रही अर्थव्यवस्था को यदि ब्याजमुक्त बनाना है तो देश को नई करवट लेनी होगी। कानूनों का जाल काटना होगा। सरल फार्मूलों से देश को पूंजी उत्पादक बनाना होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दुनिया भर में भारत को व्यापारिक देश की छवि से रंगने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्रांतिकारी दौर है।पर ये तभी सफल हो सकता है जब भारत में जातिवाद, संप्रदायवाद, नियंत्रणवाद और तमाम किस्म की बदमाशियों को धूल धूसरित कर दिया जाए। जब तक देश समाजवाद, साम्यवाद, उदारवाद जैसे मूर्खतापूर्ण विचारों के बीच झूलता रहेगा तब तक देश में आर्थिक मजबूती का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा। लोकतंत्र के इस महापर्व पर भारत की जड़ता तोड़ने के ये प्रयास होंगे तो सत्ता की मौजूदा पीढ़ी का स्वप्न जल्दी पूरा हो सकेगा।

मुखयमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी विनम्रता, मिलनसारिता, सामाजिक मुद्दों पर बेबाक टिप्पणियों,के कारण चर्चा में रहते हैं। सभी धर्मों को पर्याप्त संरक्षण देने वाली उनकी उदार छवि टकराव को टालती है। प्रशासन को लीक से हटकर चलने की प्रेरणा देकर वे उसे जनता के करीब लाते हैं। यही वजह है कि उनकी छवि का जादू लगातार कायम है।

सुनने की आदत डाल ले कांग्रेस

सत्ता के घोड़े पर चढ़े रहने के लिए कांग्रेसियों ने हर कदम पर अहसान लादने की परंपरा बना ली है। हमने देश को आजादी दिलाई, हमने ही देश का विकास किया, हमने ही देश पर बलिदान किया जैसे अनेक तर्कों को पेश करके कांग्रेसियों ने भोले भाले हिंदुस्तान को जी भरकर लूटा है। कभी राशन की लाईन में लग जाओ, कभी कानूनों के उल्लंघन के नाम पर संपत्तियां हड़प लो, कभी सरकारीकरण थोपकर जनता की जेबें तराश लो। हजारों मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेसियों की बोलती बंद हो जाती है। इसके बावजूद कांग्रेस अपनी परिपाटी को छोड़ने तैयार नहीं है। सवा सौ करोड़ के देश की मुद्रा आज भी डॉलर और पौंड के सामने भिखारी बनी खड़ी है और कांग्रेसी अहसान लादने की नादानी छोड़ने तैयार नहीं हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चे ने बच्चों की एक प्रतियोगिता में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को लालची बता दिया। कहा गया कि नेहरू के सत्ता पाने के लालच के कारण ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। इस पर कांग्रेसी बिफर पड़े। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखर प्रवक्ता केके मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने ही देश को आजाद कराया । जाहिर है जब जर्मनी के हिटलर और इंग्लैंड के एटली और चर्चिल के व्यक्तिगत विवादों की वजह से द्वितीय विश्वयुद्ध हुआ था और दोनों देश एक दुसरे के कट्टर दुश्मन थे 7 तब एक दुश्मन देश की मदद से सुभाष चन्द्र बोस ने अंग्रेजों के नाकों चने चबवा दिए थे 7 एक तो अंग्रेज उधर विश्वयुद्ध में लगे थे दूसरी तरफ उन्हें भारत में भी सुभाष चन्द्र बोस की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था 7 इसलिए वे सुभाष चन्द्र बोस के दुश्मन थे 7 जबकि नेहरू वाला कांग्रेसी धड़ा अंग्रेजों के साथ खड़ा था। इस युद्ध में विजय के लिए ब्रिटेन को संसाधन और फौजें उपलबध कराई जा रहीं थीं। आरएसएस की स्थापना २५सतंबर १९२५को नागपुर में हुई थी। जबकि दूसरा विश्व युद्ध १९३९से १९४५ तक चला। इस दौरान आरएसएस लगभग शैशव काल में ही था। एक तो अंग्रेजों के दबदबे के कारण लोग एकत्रित ही नहीं हो पाते थे दूसरे कांग्रेस के नेता कोई दूसरा संगठन खड़े नहीं होने देना चाहते थे। यही वजह है कि आज कांग्रेसी चिल्ला चिल्लाकर कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में संघ के लोग कहां थे। कांग्रेसियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि नई पीढ़ी सारी सच्चाईयों से अच्छी तरह वाकिफ है। सर ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस को अंग्रेजों के सहयोग के लिए तैयार किया था। उसी के माध्यम से लार्ड माऊंटबैटन ने सत्ता का हस्तांतरण किया। वे नहीं चाहते थे कि दुश्मन देश के समर्थन से सुभाष चंद्र बोस कोई वैकल्पिक सरकार गठित कर लें। अब आज यदि भाजयुमो के नेता नई पीढ़ी को नेहरू के लालच की कहानी सुना रहे हैं तो कांग्रेसियों को मिर्ची कयों लग रही है। ये बात सही है कि देश ने आजादी पाई नहीं बल्कि उसे ये कथित आजादी दी गई है। इसे ब्रिटेन ने अपने हाऊस आफ कामन्स में पारित एकट के तहत सत्ता हस्तांतरण के माध्यम से सौंपा था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947(Indian Independence Act 1947) युनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट में पारित वह विधान है जिसके अनुसार ब्रिटेन शासित भारत का दो भागों (भारत तथा पाकिस्तान) में विभाजन किया गया। यह अधिनियम १८जुलाई १९४७ को स्वीकृत हुआ और १५ अगस्त १९४७ को भारत बंट गया। देश को नहीं भूलना चाहिए कि अंग्रेजों ने भारत को डामिनिक इस्टेट के रूप में मान्यता दी थी। इसका मतलब था कि एक बड़े राज्य के अधीन छोटा राज्य। यही वजह थी कि जब भारत की कथित आजादी की सुबह होने वाली थी तब महात्मा गांधी नोआखाली में थे। दिल्ली में केवल नेहरू की मंडली तिरंगा फहराने पहुंची थी। जब गांधीजी कह रहे थे कि पाकिस्तान उनकी लाश पर बनेगा तो फिर नेहरू को ऐसी कया जल्दी थी कि उन्होंने भारत पाक विभाजन मंजूर कर लिया और कुर्सी हथिया ली। यही वजह थी कि नेहरू की नीतियों से नाराजगी की आवाज तेज होती गई और २१अकटूबर १९५१को जनसंघ अस्तित्व में आया। भाजपा के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल कहते हैं कि देश में जो भारत केन्द्रित तंत्र खड़ा होना था वह केवल इसलिए नहीं पनप सका कयोंकि नेहरू तो अंग्रेजों की नीतियों का ही परचम उठाए हुए थे। वास्तव में नेहरू की नीतियों को गलत ठहराने की आवाज आज नई नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी की बात कहने वाले कांग्रेसियों ने जनसंघ के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ कैसा सलूक किया इसकी परतें खोली जाएं तो उसकी तुलना में भाजपा की सरकारों ने तो कांग्रेसियों के प्रति बड़ा सौहार्द्रपूर्ण रवैया अपनाया हुआ है। भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने अपनी पारंपरिक आवाज को ही नई पीढ़ी तक हस्तांतरित करने का उपक्रम किया है, जो वे पीढ़ियों से करते रहे हैं। लोकतंत्र का ढोंग करने वाले परिवारवादी कांग्रेसियों को इसे सुनने की आदत बना लेनी चाहिए। देश की नई पीढ़ी कांग्रेस की खोखली नीतियों से दूर हो चुकी है। आगे चलकर वह आज की कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह पर भी उतारू हो सकती है।

देश के स्वास्थ्य पर भी सर्जिकल स्ट्राईक की जरूरत:डॉ.पारे

भोपाल(पीआईसीएमपीडॉटकॉम)। भारत की मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एक महान देश को लाचार बना रहीं हैं। मोदी सरकार को इन पर सर्जिकल स्ट्राईक करके इसमें आमूल चूल बदलाव करना होगा। इस मुद्दे पर चुप्पी देश को भारी मंहगी पड़ रही है। युवाओं का देश भारत आज बीमार है और इसे स्वस्थ बनाने के लिए हम जो संसाधन झोंक रहे हैं उनसे हमारी प्रगति प्रभावित हो रही है। ये विचार एलोपैथिक और प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ.अंबर पारे ने व्यक्त किए।

राजधानी के स्वराज भवन सभागार में अक्षर प्रभात जीव संरक्षण की ओर से आयोजित व्याख्यान माला में उन्होंने ये विचार व्यक्त किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में अक्षर प्रभात ट्रस्ट के रामगोपाल बंसल, रामनिवास गोलस और आनंद मार्ग संप्रदाय के कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। इस अवसर पर शाकाहार को प्रोत्साहित करने वाली पुस्तक (हम भी पशु हैं क्या) का विमोचन किया गया।

लाईलाज बीमारियों के इलाज के लिए लगभग 150 गांवों में मेडिकल कैंप लगाने वाले डॉ.अंबर पारे ने कहा कि देश के बीमार स्वास्थ्य ढांचे से निपटने के लिए हमें एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी सभी का मिला जुला प्रयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत में हर व्यक्ति घरेलू दवाओं की जानकारी रखता है लेकिन उसे इतना ज्यादा डरा दिया जाता है कि वो जड़ी बूटियों और चूरन चटनी को खलनायक मानने लगता है। बाजारू सोच ने आम नागरिकों की जीवनशैली को इतना अधिक प्रदूषित कर दिया है कि लोगों की जीवन शक्ति घट गई है। नए नए प्रकार के रोग बढ़ रहे हैं। इसके लिए देश में व्यापक जन जागरण अभियान चलाना होगा। मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे की गड़बड़ियों को उजागर करने के का जिम्मा सरकार को अपने हाथों में लेना होगा और इस क्षेत्र में उसी तरह सर्जिकल स्ट्राईक करनी होगी जैसे पाकिस्तान के खिलाफ की गई थी। खासतौर पर हृदय रोगियों को तरह तरह से भयाक्रांत किया जा रहा है और उनसे भारी रकम वसूल की जा रही है।

आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोगी देश है। यहां दवाओं और इलाजों पर हर साल पांच लाख करोड़ से भी ज्यादा धन खर्च होता है। भारत को ठंडे देशों के लिए बनी दवाईयों की प्रयोगशाला बना दिया गया है। जबकि वे दवाईयां हमारी प्रकृति, खानपान और मनोदशाओं के लिए दुश्मन साबित हो रहीं हैं। उन्होंने कहा कि साईंटिफिक क्वांटम कन्शसनेस, सुपर कान्शियस एवं सब कांन्शियस, साईंस बियांड साईंस, योग एंड साईंटिफिक हीलिंग थैरेपी, स्पीरीचुअल साईंटिफिक हीलिंग पर अनुसंधान करके जो तरीके विकसित किए गए हैं उनसे असाध्य बीमारियों का भी इलाज संभव है।

उन्होंने कहा कि 99 फीसदी चिकित्सक और मरीज इंसान के शरीर के लक्षणों के आधार पर इलाज करते हैं। जबकि इसकी जड़ हमारे प्राण शरीर में छुपी होती है। इसके लक्षण साल भर या छह महीने पहले ही नजर आने लगते हैं। इसके बावजूद डाक्टर पैथालाजी रिपोर्ट के आधार पर मरीज को क्लीन चिट दे देते हैं। बाद में रोग को असाध्य घोषित कर दिया जाता है। डॉ.पारे ने कहा कि हम प्राकृतिक चिकित्सा से शरीर के रोग हटाने पर जोर देते हैं जिससे मरीज का स्थाई इलाज होता है। व्याख्यानमाला के दौरान सफल इलाज पाने वाले पूजा, सोनल और कई अन्य रोगियों के अनुभव भी साझा किए गए। अंत में रामनिवास गोलस ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया।

मध्यप्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के बीच युवाओं ने किया बेरोजगार सेना का गठन

भोपाल। मध्यप्रदेश में बेरोज़गारों की तादाद बढ़ती जा रही है. हालात ऐसे हैं कि कुछ युवाओं ने बेरोजगारी रोकने के लिए ठीक राष्ट्रीय युवा दिवस पर बेरोजगार सेना का गठन किया है. सरकार का कहना है कि केन्द्र और राज्य दोनों प्रयासरत हैं और हालात कांग्रेस के शासन से बहुत अच्छेहुए हैं.

एक अनुमान के मुताबिक राज्य में हर छठे घर में एक युवा बेरोजगार है और हर सातवें घर में एक शिक्षित युवा बेरोजगार बैठा है. सत्यप्रकाश त्रिपाठी केमेस्ट्री में एमएससी हैं, रोज़गार की आस में दो तीन डिग्री और हासिल कर ली, लेकिन फिलहाल बेरोज़गार हैं. त्रिपाठी ने कहा, मैं सोशियोलॉजी में यूनिवर्सिटी टॉपर हूं, ग्रामीण विकास में डिप्लोमा लिया, बीएड, एमफिल भी हूं, रोज़गार नहीं मिला. कई जगह कोशिश की लेकिन भ्रष्टाचार या कुछ और वजह थी कि चयन नहीं हुआ.

सरकारी आंकड़े कहते हैं, मध्यप्रदेश में लगभग एक करोड़ इकतालीस लाख युवा हैं. पिछले दो सालों में राज्य में तिरेपन प्रतिशत बेरोजगार बढ़े हैं. दिसंबर दो हजार पंद्रह में पंजीकृत बेरोजगारों की संखया पंद्रह लाख साठ हजार थी जो दिसमबर दो हजार सत्रह में तेईस लाख नबबे हजार हो गयी है. प्रदेश के अड़तालीस रोजगार कार्यालयों ने मिलकर दो हजार पंद्रह में कुल तीन सौ चौंतीस लोगों को रोजगार उपलबध कराया है.

बेरोज़गार सेना के अध्यक्ष अक्षय हुंका ने कहा, हमारी एक मांग है, जैसे मनरेगा का कानून बनाया, वैसे शिक्षित बेरोजगारों के लिये शिक्षित युवा गारंटी कानून बनाएं. मध्यप्रदेश में बड़ी-बड़ी डिग्री ले लीजिये लेकिन नौकरी नहीं मिलती जिसकी गलती सरकार और उसकी पॉलिसी की है. रोज़ी कमाना और जिसके लिये पढ़ाई की बड़ी डिग्री अर्जित करने में उसे पकौड़े का ठेला लगाना पड़ रहा है, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता. देश के प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं तो बेरोजगारों पर हथौड़ा चला रहे हैं

कुछ दिनों पहले सागर जिले में देवरी तहसील के राजेन्द्र बड़कुल की बिटिया रागिनी की शादी के लिये छपे कार्ड में भाई अनुराग ने लिखवाया मेरी भूल कमल का फूल कयोंकि दो हजार दस में स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर नियुक्त हुए भाई की नौकरी दो हजार सत्रह में चली गई, ऐसे करीब चार सौ तेहत्तर कर्मचारी थे.

मध्यप्रदेश में रोज़गार कार्यालय है, दीपेन्द्र जैसे कई युवा यहां आते थे. लेकिन अब यहां भीड़ नहीं जुटती, एमए कर रहे दीपेन्द्र ने पटवारी की परीक्षा दी थी जिसमें हज़ार पदों के लिये लाखों उममीदवारों ने फॉर्म भरा. दीपेन्द्र ने बताया, मैंने पटवारी की परीक्षा दी, फॉरेस्ट की दी, संविदा की तैयारी में हूं. पटवारी की परीक्षा में नौ हजार दो सौ अड़तीस पदों की भरती निकली थी, तकरीबन बारह लाख फॉर्म भरे गये, अब मेरिट पर लिस्ट बनेगी. राज्य में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, पद कम निकलते हैं.

मध्यप्रदेश में सरकार के पास ही लगभग एक लाख से अधिक वैकेंसी है, लेकिन लोगों को रोज़गार दिलाने वाला दफतर तक खाली है. जिला रोज़गार कार्यालय भोपाल के प्रबंधक के एस मालवीय ने कहा, बेरोजगारी की समस्या तो बढ़ती जा रही है, सरकारी नौकरियां घट तो रही हैं, हर साल लाखों बच्चे निकलते हैं.

देश में शिक्षित बेरोजगारी के खिलाफ कोई कानून नहीं है, बेरोजगारों की तादाद बढ़ रही है लेकिन फिर भी सरकार समस्या को समस्या मानने से इनकार कर रही है, आंकड़े उसे कुतर्क लगते हैं. विपक्ष का आरोप है रोज़गार मंत्री-पुत्रों को ही मिल रहा है. सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, हम केवल रोजगार कार्यालय के आंकड़े से रोजगार को नहीं देख सकते. मैं इंजीनियर हूं, राजनीति में आया, ऐसा करना तर्क नहीं कुतर्क है. पढ़ाई का मतलब है ज्ञान.वहीं कांग्रेस के मुखय प्रवक्ता केके मिश्रा ने कहा, सरकार के पास वो इंफ्रास्ट्रकचर नहीं जिससे रोजगार का सृजन हो, जो कारोबार हैं वो बंद हो रहे हैं. नोटबंदी का भी असर पड़ा है, विषम परिस्थितियों में रोजगार सरकार शबदों मे देने की कोशिश कर रही है

इन सबके बीच बेरोजगार सेना एक मिस्ड कॉल नंबर देकर शिक्षित युवाओं की सेना बनाने में जुटी है. मांग है कि एक शिक्षित युवा गारंटी कानून बनाया जाए.

राजभवन में गणतंत्र दिवस स्वागत समारोह संपन्न

भोपाल .गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजभवन में स्वागत समारोह का आयोजन हुआ। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने मुखयमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सहित समस्त आगंतुकों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएँ दीं। राज्यपाल तथा मुखयमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को शाल एवं श्रीफल भेंट कर सममानित किया।

आयोजन स्थल पर विशाल पांडाल लगाया गया था। पारंपरिक तरीके से हटकर आगंतुकों ने राज्यपाल महोदया से मुलाकात की। उन्हें राज्य की बेहतरी के लिए सुझाव भी दिए। ऐसा आत्मीय आयोजन पहली बार देखा गया।

समारोह में लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, सांसद श्री आलोक संजर, पूर्व मुखयमंत्री श्री बाबूलाल गौर, विधायकगण, पूर्व सांसद श्री कैलाश सारंग, निगम-मंडलों के अध्यक्ष, मुखय सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुकला, विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, पत्रकार तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। प्रदेश के लोगों ने भी राज्यपाल को शुभकामनाएं दीं।

सिद्धि विनायक ज्वेलर्स

69वें गणतंत्र दिवस पर
सभी राजधानीवासियों
को
हार्दिक शुभकामनाएं

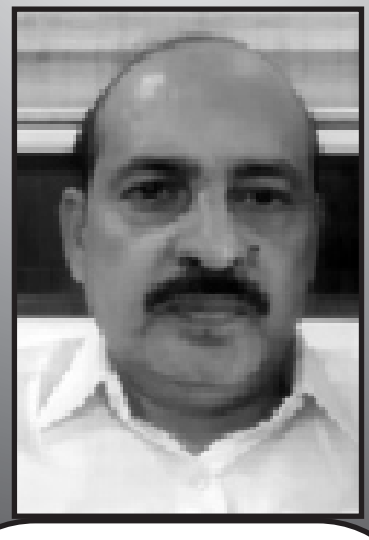

संजय तिवारी
9425008012

सतर्क रहें, सुरक्षित रहें

मध्यप्रदेश पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए किए हैं
ऐसे इंतजाम, जिनसे हर कदम आपको मिल सके सुरक्षा

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

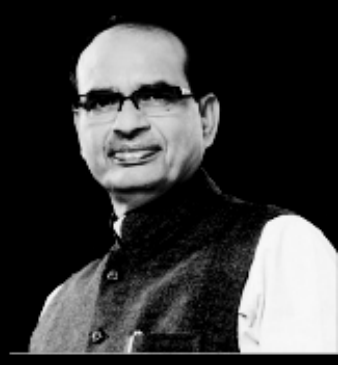

महिला डेस्क – सभी थानों में महिलाओं की शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई

हेल्पलाइन 1090 – राज्यस्तरीय हेल्पलाइन में महिलाएं निडर होकर करें शिकायत

सोशल मीडिया – महिला अपराध शाखा का फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, मैत्री एप में अपना लोकेशन बताने की सुविधा

निर्भया पेट्रोलिंग – स्कूल-कॉलेज, हॉस्टल, पार्क, मार्केट के पास महिला पुलिस की पेट्रोलिंग

महिला थाना – भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना, सागर, जबलपुर, रीवा, रतलाम और कटनी में

सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग – स्कूल-कॉलेज में छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण

जनसंवाद शिविर – जागरूकता और जानकारी देने के साथ समस्या समाधान के लिए स्कूल-कॉलेजों में शिविरों का आयोजन

फास्ट ट्रेक कोर्ट – महिलाओं के लिए त्वरित सुनवाई के लिए सभी 51 जिलों में फास्टट्रेक कोर्ट

परिवार परामर्श केन्द्र – पारिवारिक विघटन रोकने के लिए प्रदेश में परामर्श केन्द्रों की स्थापना

MPeCop मोबाइल एप – संकट के समय युवती के पांच परिजनों एवं डायल 100 को पहुंच जायेगा SMS

महिला हेल्पलाइन 1090 | MPeCop मोबाइल एप | डायल 100

मध्यप्रदेश पुलिस - हर कदम आपके साथ

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2017

नरेंद्र मोदी के भ्रमपूर्ण वादे अगले आम चुनावों में बनेंगे गले की हड्डी

चन्दन शर्मा

लोकसभा चुनाव के वक्त जनता से वोट मांगते हुए नरेंद्र मोदी ने आर्थिक मोर्चे पर कई वादे और दावे किए थे. अपना तीन चौथाई कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार इनमें से कई वादे पूरे कर चुकी है. लेकिन कइयों के साथ ऐसा नहीं है. इनमें विदेशों से कालाधन वापस लाने और विकास दर बढ़ाने जैसे वादे शामिल हैं. इसे देखते हुए सवाल उठना लाजिमी है कि आम लोगों के लिहाज से मोदी सरकार का शासन कैसा माना जाए.

विदेशों में जमा कालेधन की वापसी पर सरकार की गंभीरता समझने के लिए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का तीन साल पहले दिया गया बयान याद करना चाहिए. दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त एक चैनल से उन्होंने कहा था कि बाहर से कालाधन लाकर हर परिवार के खाते में पंद्रह लाख रुपये जमा करने वाला वादा एक 'जुमला' था. हालांकि सच्चाई ये है कि नरेन्द्र मोदी ने स्वयं कभी ये वादा नहीं किया था ।इसका मतलब यह हुआ कि इस वादे के आधार पर नरेंद्र मोदी का समर्थन करने वाले इस सरकार से निराश हुए हैं. अमित शाह ने तब कहा था कि सब जानते हैं कि कोई सरकार इन पैसों को लोगों को देने के बजाय देश के विकास में खर्च करना पसंद करेगी. हालांकि मोदी सरकार ने कभी नहीं बताया कि उसके प्रयासों से देश में कितना कालाधन वापस लौट चुका है.

नरेंद्र मोदी का दूसरा बड़ा वादा दो करोड़ रोजगार देने का था. रोजगार पर किसी विस्तृत सर्वेक्षण के अभाव में इस वादे का मूल्यांकन करना काफी कठिन है. लेकिन लेबर बयूरो के विभिन्न सर्वेक्षणों का औसत लेने पर पता चलता है कि आठ फीसदी की हिस्सेदारी वाले संगठित क्षेत्र में मोदी सरकार हर साल औसतन कुछ लाख रोजगार ही पैदा कर सकी है. एक अन्य आकलन के अनुसार असंगठित क्षेत्र में यदि इसी दर से रोजगार पैदा हुआ मान लें तो भी कुल आंकड़ा दावों से बहुत पीछे है. ऊपर नोटबंदी के बाद के हालात और खराब हुए हैं.

बेरोजगारी की समस्या से सरकार को आगाह करते हुए 'करियर्स नामक मैगजीन के प्रकाशक महेश्वर पेरी ने पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला खत लिखा था. इस पत्र में उन्होंने कहा था कि देश को यदि युवा शक्ति का लाभ उठाना है तो अगले एक दशक में चार करोड़ रोजगारों का इंतजाम करना होगा. इसका मतलब देश में हर साल अभी का लगभग आठ गुना (तीन करोड़ से ज्यादा) रोजगार पैदा करने होंगे. जानकार इस लक्ष्य को मौजूदा हालात में नामुमकिन-सा मानते हैं.

अर्थव्यवस्था की विकास दर के बारे में नरेंद्र मोदी ने पिछले चुनाव में दावा किया था कि यह दर बढ़ाकर फीसदी कर दी जाएगी. उन्होंने इसे बहुत जरूरी बताते हुए कहा था कि ऐसा होने से लोगों की समृद्धि बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. लेकिन हाल के एक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2017में देश की विकास दर मुश्किल से फीसदी तक जा सकती है. यह आंकड़ा मनमोहन सिंह के आखिरी वर्ष की विकास फीसदी (संशोधित) से थोड़ा ही ज्यादा होगा. यानी जी-तोड़ कोशिश के बाद भी सरकार विकास दर बढ़ाने का अपना वादा पूरा करने में नाकामयाब रही है.

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के प्रयासों की बात करें तो यह मानना पड़ेगा कि मौजूदा सरकार के राज में अब तक कोई बड़ा घोटाला सामने नहीं आया है. हालांकि जानकारों के मुताबिक यह जरूर है कि सरकार लोकपाल, सीबीआई जैसी भ्रष्टाचार निरोधी संस्थाओं को मजबूत करने में अब तक नाकाम रही है.

लोगों को मजबूत बनाने वाली शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों के मामले में भी केंद्र सरकार का प्रदर्शन निराशाजनक कहा जा सकता है. कई लोग मानते हैं कि पिछले दो-तीन साल में छात्रों के बढ़े असंतोष का मुखय कारण शिक्षा पर होने वाली खर्च में की गई कटौती है. स्वास्थ्य क्षेत्र में भी पर्याप्त राशि के अभाव में सरकार ने अपने हाथ बांध रखे हैं. गरीबी उन्मूलन के साथ समाज के वंचित तबकों की मजबूती के लिए खर्च होने वाली राशि में भी कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो पायी है. जानकारों के अनुसार केंद्र सरकार अपनी राजकोषीय सेहत दुरुस्त करने के लिए हर साल अपना खर्च लगातार घटा रही है. इसके चलते पिछले चार साल में केंद्र का बजट खर्च जीडीपी के फीसदी से घटकर फीसदी हो गया है. अब सरकार की आमदनी बढ़े बिना खर्च में बढ़ोतरी हो पाना संभव नहीं लग रहा है.

मोदी सरकार किसानों से जुड़े कई वादे भी अब तक पूरा करने में नाकाम रही है. के चुनाव के समय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यदि उनकी सरकार बनी तो किसानों को फसल की लागत का डेढ़ गुना दाम दिलाया जाएगा. हालांकि अभी तक सरकार इस वादे पर कभी गंभीर नहीं दिखी है. नोटबंदी ने उल्टा किसानों की हालत पहले से खराब कर दी है. जानकारों के अनुसार किसानों के आंदोलन और कर्ज माफी की मांग का मुखय कारण यही रहा है. हर खेत को सिंचाई देने का वादा भी अभी काफी दूर है. फसल बिक्री के लिए बाजार को विविध और विकसित करने के मामले में भी सरकार को कुछ खास सफलता नहीं मिली है.

बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सरकार का प्रदर्शन हालांकि मिला-जुला माना जा सकता है. सड़क, विमानन परिवहन, बिजली, गैस आदि के क्षेत्र में उसका काम बढ़िया माना जा रहा है. लेकिन रेलवे और दूरसंचार के क्षेत्र में सरकार की कोशिश अभी तक अपना असर नहीं दिखा पाई है. ये क्षेत्र करोड़ों नागरिकों की जिंदगी को काफी प्रभावित करते हैं. जानकारों के अनुसार अर्थव्यवस्था और बैंकों की दशा खराब रहने से देश के बुनियादी ढांचे में उममीद के मुताबिक निवेश नहीं हो सका है.

सरकार को गांवों, किसानों और युवाओं की चिंता करनी चाहिए

वैसे जानकारों का मानना है कि इन कुछ नाकामयाबियों को छोड़ दें तो आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार का काम बढ़िया रहा है. हालांकि दिक्कत यह है कि इनके ज्यादातर फैसले दीर्घकालिक हैं यानी वे लंबे समय में अपना असर दिखाएंगे. ऐसे लोग यह भी मानते हैं कि जो फैसले अपना असर दिखा भी रहे हैं उनका गांव, किसान और युवा से ताल्लुक ही है. ऐसे में कई विश्लेषकों को आशंका है कि कहीं सरकार को अगले आम चुनाव में इसका खामियाजा न उठाना पड़े.

आलोचकों के अनुसार केंद्र सरकार मंत्रियों के कम अनुभव के चलते अभी भी नीतियों में उलझी हुई है जिसके चलते उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहा है. दूसरी ओर खर्च में कटौती की मजबूरी के चलते सरकार के पास खर्च के लिए जरूरी धन नहीं है. इससे वह गांव, किसान और युवाओं का ख्याल नहीं रख पा रही है. गुजरात चुनाव में ग्रामीण इलाकों में भाजपा को मिले झटके को आलोचक केंद्र सरकार के लिए एक सबक मानते हैं. इनके अनुसार अगले लोकसभा चुनाव में केंद्र में दोबारा सत्तारुढ़ होने की सरकार की ख्वाहिश को ये वर्ग पूरा होने से रोक सकते हैं. जानकारों के अनुसार सरकार के पास अभी भी एक साल का वक्त है जिसमें वह अपने फैसलों से इन लोगों की नाराजगी दूर कर सकती है. ऐसे में केंद्र का अगला बजट लोकलुभावन होने के आसार हैं.इसके बावजूद विचारों और वादों के भ्रम सरकार को चुनौतीपूर्ण साबित होंगे।

दस रुपये के सभी चौदह तरह के सिक्के वैध और मान्य हैं :आरबीआई

नई दिल्ली। आम जनता और व्यापारियों के बीच 10 रुपये के सिक्कों की वैधता से जुड़े शक को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक बार फिर सफाई दी है. बुधवार को आरबीआई ने बताया कि दस रुपये के सभी सिक्के पूरी तरह वैध हैं और उनका बेझिझक लेन-देन किया जा सकता है. आरबीआई ने सभी बैंकों को अपनी शाखाओं में दस रुपये के सिक्कों को स्वीकार करने का निर्देश दिया है.

आरबीआई ने आम लोगों के बीच दस रुपये के सिक्कों की डिजाइन को लेकर बनी आशंका को भी दूर किया है. उसने कहा है कि अब तक अलग चौदह डिजाइनों के सिक्के जारी किए गए हैं जो बाजार में एक साथ चल रहे हैं. आरबीआई के मुताबिक, 'समय-समय पर जारी इन सिक्कों में देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े विषयों को दिखाने की खूबियां हैं.'

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में वित्त राज्यमंत्री शिवप्रताप शुकला ने आरबीआई को बैंकों द्वारा दस रुपये के सिक्कों को स्वीकार न करने की शिकायत मिलने की जानकारी दी थी. इससे पहले भी आरबीआई ने दस रुपये के सिक्कों को वैध बताया था।

६९वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं
हरिओम मशीनरी स्टोर्स
यूनियन बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, इछावर
आर्गेनिक कृषि उत्पाद
(मॉरलग्रीन) एवं मोटरपंप मिलने
का एकमात्र विश्वसनीय स्थान
प्रो.
महेन्द्र सिंह खाती
मो.नं.-9098350056
हमारे साथ आईए, मुनाफे वाली कृषि पाईए

कोरेगांव में हुआ दलितों और अरब सैनिकों का युद्ध

पिछले दिनों 1 जनवरी को बड़ी संखया में दलितों ने कोरेगांव में शौर्य दिवस मनाया और जब कुछ हिन्दू संगठनों ने इसका विरोध किया तो वे सरे आम हिंसा पर उतर आए बंद का आह्वान कर बहुत सारी सरकारी तथा निजी संपत्तियों का भी नुकसान किया। यह सब किया गया एक झूठे ऐतिहासिक मिथक के आधार पर। जिसके सभी सत्य प्रमाण भी उपलबध है। आइए जानते है कोरेगांव का लड़ाई का असली सच।

कोरेगांव का लड़ाई मराठाओं और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। यह अंतिम मराठा युद्ध था जिसके बाद अंग्रेजों की जड़े भारत में और गहरी हो गई थी। लेकिन कुछ लोग इस युद्ध को दलित बनाम ब्रामहण के रूप में पेश कर इसे दलितों के विजय के रूप में प्रचारित कर रहे है और बकायदा इसको शौर्य दिवस के रूप में भी मना रहे है जो कि सरासर इतिहास के साथ छेड़छाड़ है।

दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में मराठा सेनाओं ने बकायदा बीस हजार सैनिकों की फौज लेकर पूना पर धावा बोल दिया। उस समय अंग्रेजो के पास एक हजार से भी कम सैनिक थे, जिनमें महार सैनिकों की संखया बहुतायत में थी। युद्ध एक दिन से कुछ ज्यादा समय तक चला। अंग्रेजो ने संकट की घड़ी में महार सैनिकों को ही आगे कर दिया परिणाम स्वरूप बहुत सारे महार मारे गए।

दोनों तरफ से कौन-कौन लड़े-

अगर अंग्रेजों के तरफ से सबसे ज्यादा मरने वाले में महार थे तो मराठों की तरफ से सबसे ज्यादा मरने वाले में अरब सैनिक थे।

विजय किसकी हुई-

कई लोग इसे सीधे अंग्रेजो की विजय मानते है जबकि सच्चाई ऐसा नहीं है। रास्ते मे मराठाओं को जब अंग्रेजो ने रोका तब मराठाओं ने मुलाबले के लिए केवल चंद सैनिकों भेजा । युद्ध और आगे बढ़ता लेकिन तभी मराठाओं को एक बहुत बड़ी अंग्रेजी सेना के आने की सूचना मिल गई। उनको भी समझ आ गया कि तोप के सामने तलवार ज्यादा देर नहीं टिक सकती। यह सोचकर कि इस तरह युद्ध करने से हमलोगों का ज्यादा नुकसान हो सकता है उन्होंने सभी सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दे दिया। इसके बावजूद उन्होंने अंग्रेजो का बहुत नुकसान कर दिया था।

जेमस ग्रैंड डफ़ नामक अंग्रेज अधिकारी एवं इतिहासकार लिखते है कि शाम को अँधेरा होने के बाद जितने भी घायल सैनिक थे उनको लेकर कप्तान स्टैंटन गांव से किसी प्रकार निकले और पूना की ओर चल पड़े। रास्ते में राह बदल कर वो सिरोर की ओर मुड़ गए।

कई लोग बिना सोचे-समझें अंग्रेजी राज को दलितों के लिए भला कहने लगते है जबकि सच्चाई इसके उलट है। अंग्रेजो ने फुट डालो और राज करों की नीति के तहत दलितों का केवल अपने अनुसार उपयोग किया।

अगले दिन सुबह सभी मृत और घायल सैनिकों के साथ वो अपने गंतव्य पहुंचे। अंग्रेजी सेना के एक तिहाई घोड़े या तो मारे जा चुके थे अथवा लापता थे।

माउंटस्टुआर्ट एलफिन्स्टन ने इसे पेशवा के लिए छोटी सी जीत बताया फिर ये महारो के शौर्य का प्रतीक किस इतिहासकार ने बनाया ऊपर वाला ही जाने ।।

युद्ध लड़ना महारों का सैनिक कर्तव्य या प्रतिशोध-

चूँकि आक्रमण मराठाओं ने किया था न कि महारो ने अत: महारो द्वारा प्रतिशोध लेने के लिए आक्रमण करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चूँकि सबसे ज्यादा मरने वाले में इधर महार थे तो उधर अरब सैनिक थे इस प्रकार देखे तो भिड़ंत महारो और अरबों के बीच हुई थी। लेकिन वास्तव में दोनों तरफ के सैनिक किसी प्रतिशोध में नहीं बल्कि अपने-अपने मालिकों के लिए लड़े थे अत: हार या जीत सैनिकों की नहीं बल्कि मालिकों की होनी चाहिए। अत: महारों का युद्ध लड़ना उनका सैनिक कर्तव्य था ना कि कोई प्रतिशोध।

युद्ध के बाद महारों की स्थिति-

युद्ध के बाद महारों की तत्कालीन सामाजिक स्थिति में कोई बदलाव आया या नहीं इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता अपितु इसके उलट अंग्रेजो ने महारों को अछूत मानकर उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। कयोंकि धीरे-धीरे महारों में भी देश के प्रति चेतना जगने लगी थी और क्रांति में वे अंग्रेजों के विरुद्ध भी लड़े थे।

चूँकि अंग्रेजो ने दलितों की सेना भर्ती में रोक लगा दी थी अत: इस रोक को हटाने के लिए पहली पीढ़ी के दलित नेताओ ने अंग्रेजो को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने इस युद्ध का जिक्र करते हुए लिखा कि आपके लिए बलिदान देने वाले में दलित भी है। लेकिन इसका कोई प्रभाव अंग्रेजो पर नहीं पड़ा।

चूँकि जब अंग्रेजो को ज्यादा सैनिकों की आवश्यकता महसूस हुई तब कुछ समय के लिए प्रतिबंध हटा लिया गया लेकिन युद्ध के बाद अंग्रेजो ने पुन: प्रतिबंध बहाल कर दिया था। इस स्थिति को देखते हुए भीम राव अंबेडकर ने शासन से दलितों को फायदा दिलाने के लिए इधर-उधर हाथ पांव मारना शुरु कर दिया था। इसी क्रम में उनको कोरेगांव में एक ऐसा स्मारक मिला जिसमें मारे गए शहीदों के नाम लिखे थे जिसमें कई नाम महारों के थे। स्तंभ का शिलालेख घोषित करता था कि कप्तान स्टॉन्टन की सेना ने पूर्व में ब्रिटिश सेना की गर्वित विजय हासिल की।

एक जनवरी को अंबेडकर ने उस विजय स्तंभ पर महारो के नाम खुदवाए हुए संगमरमर का एक शिलालेख लगवाया और इस बात को मुद्दा बनाते हुए इसे महारो के शौर्य के रूप में प्रचारित कर अंग्रेजो से एक अलग महार रेजिमेंट की स्थापना करने की मांग की। हालांकि उनकी यह मांग भी आजादी के बाद ही पूरी हो सकी। उसी दिन के बाद से हर साल दलित नेताओं ने यहाँ शौर्य दिवस मनाना शुरू किया और बिना सोचे समझे इस युद्ध को दलितों का ब्रामहण पेशवाओं के प्रतिशोध के रूप में प्रचारित करना शुरू किया।

अंग्रेज दलितों के लिए कितने भले-

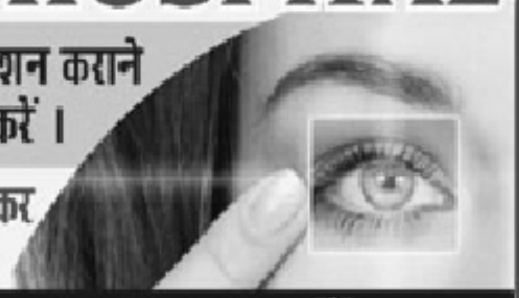

कई लोग बिना सोचे-समझें अंग्रेजी राज को दलितों के लिए भला कहने लगते है जबकि सच्चाई इसके उलट है। अंग्रेजो ने फुट डालो और राज करों की नीति के तहत दलितों का केवल अपने अनुसार उपयोग किया।

विलियम डिग्बी और माइक डेविस के शोध बताते है कि अंग्रेजी राज से पहले के इतिहास के उलट गुलाम भारत के दो सौ सालों के दौरान अकाल और भुखमरी की वजह से करोड़ों लोग असमय मौत के मुंह में समा गए।

अमर्त्य सेन की मानें तो अकाल पर होने वाली मौतों की वजह अनाज खरीद पाने की सामर्थ्य का न होना था. तो कया यह पूछा जा सकता है कि इस 'भले' अंग्रेजी साम्राज्य में मरने वाले ये गरीब और फटेहाल लोग दलित और कमजोर तबकों से नहीं थे तो भला और कौन थे?

यानी दलित अस्मिता की राजनीति के लिए जो ब्रिटिश राज 'भला' था, आम दलितों के लिए वही मौत का कहर बनकर बरपा था।

इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर कोई दलित कोरेगांव विजय को अपना शौर्य समझता है तो न केवल वो देशद्रोही है बल्कि वो अपने उन पूर्वजों का भी अपमान कर रहा है जिन्होंने अंग्रेजी राज्य से लड़ते हुए अपनी कुर्बानी दी है। अगर उन भटके हुए लोगो के आखों पर से पर्दा उठाना है -- --आलोक बिहार।

(पेज एक का शेष भाग)

सरकारी योजनाओं का लक्ष्य पूरा करने में हिचकें नहीं-योगेन्द्र सिंह

उन्होंने कहा कि जो अधिकारी बार बार कहते हैं कि उन्हें अपना काम निपटाने के लिए देर रात तक ब्रांच में ही बैठना पड़ता है वे यदि निजी जीवन और बैंकिंग जीवन को अलग अलग करके काम करेंगे तो उन पर काम का दबाव कभी नहीं बढ़ेगा। यदि बैंक का लीडर अपनी टीम बनाकर काम बांटे तो किसी पर लोड नहीं पड़ेगा और बैंक उत्तरोतर प्रगति करता रहेगा।

उन्होंने कहा कि बैंक की साख बढ़ाने के लिए हमें कभी अपने ग्राहकों को झूठे वादे नहीं करने चाहिए। उन्हें उचित सलाह दें ताकि उनकी पूंजी का बेहतर प्रबंधन हो सके। ये काम सार्वजनिक क्षेत्र के ही बैंक अच्छा कर सकते हैं। जो लोग बैंकिंग के दौरान तनावों से घिर जाते हैं उनके लिए श्री सिंह ने कहा कि हर समस्या का उचित समाधान जरूर होता है। यदि हम लगातार सीखते रहने की ललक रखेंगे तो हमें समस्या के समाधान भी मिल जाएंगे।

प्रबंधन के सामने अधिकारियों कर्मचारियों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए यूनियन बैंक आफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभात सकसेना ने कहा कि सरकारी बैंकों की स्थिति आज भी बहुत अच्छी है। आंकड़ों को जिस भयावह अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है उससे लगता है कि मानों ये बैंक बस डूबने ही वाले हैं। उन्होंने कहा कि यूनियन की ओर से बैंकों के प्रबंधन और सरकारी प्रतिनिधियों से जो अनुबंध किए गए हैं उनके अनुसार बैंकों में स्टाफ बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैंकों के संविलियन का हो हल्ला मचाया जा रहा है लेकिन जो स्थितियां नजर आ रहीं हैं उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि वर्ष 2020 तक ये मर्जर संभव नहीं है। बैंकों के कारोबार में तेजी से सुधार हो रहा है। नए तरीकों ने बैंकिंग पर बोझ घटाया है। यदि तकनीकी आधार पर कामकाज को बढ़ावा दिया जाए तो बैंक अपने डूबत ऋणों से भी आसानी से निपट लेंगे। उन्होंने कहा कि बैंकों को चौपट करने वाले प्रयासों का लगातार विरोध किया जाएगा और बैंकों को लूटने वाले प्रयास कारगर नहीं होने दिए जाएंगे। इसके लिए बैंकों के आफिसर्स और कर्मचारी लगातार प्रबंधन का सहयोग कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ यूनियन बैंक आफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव अभय सिन्हा ने कहा कि बैंकों में बढ़ते तकनीकी दबाव के चलते कम अनुभवी अधिकारियों को भी ब्रांच मैनेजर बनाना पड़ रहा है। हमारे सामने चुनौती है कि हम ग्राहकों के वित्तीय प्रबंधन को भी कैसे बढ़ावा दें। ऋण देते समय हमें दस्तावेजी करण पर भी जोर देना होगा। यदि हमने ठीक तरह लोन दिए हैं तो कोई वजह नहीं कि लोन की वापिसी समय पर न हो। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंक अपना काम ठीक तरह कर रहे हैं। नए वित्तीय तौर तरीके प्रचलन में आ जाने के बाद हम और भी ज्यादा कारगर तरीके से जनता की सेवा कर सकेंगे।

जबलपुर यूनियन बैंक के क्षेत्रीय सचिव श्री वाणी ने कहा कि क्रेडिट बैंकिंग को आमतौर पर कठिन और पेचीदगी भरी बैंकिंग कहा जाता है। इसके बावजूद यदि हम इसे सीख लें तो बैंकों की आय भी बढ़ेगी और हम लोगों की सेवा के लिए भी ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। कार्यक्रम के प्रथम सत्र के अंत में रीवा इकाई के प्रभारी वीरेन्द्र प्रसाद ने आभार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बैंक के सभी अधिकारी और कर्मचारी हम सभी प्रबंधन के ही हिस्से हैं। इसलिए समस्याओं का समाधान भी हमें ही निकालना होगा। उन्होंने बैंक के क्षेत्रीय महाप्रबंधक योगेन्द्र सिंह के सूत्र वाक्य समान गाने का सुमधुर गायन किया। उन्होंने कहा कि इस गाने में तुझको चलना होगा की सीख दी गई है। बैंकिंग आज जिस दौर में आ गई है हमें उन हालात में और बेहतर प्रबंधन के तरीके विकसित करने होंगे ताकि हम जन बैंकिंग के अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें।

इस अवसर पर संयुक्त सचिव महेश पहलाजानी, सचिव राजेश मेहर, सौरव पाटिल, सुबोध कुमार, गौरव तिवारी, दीपिका मालवीय, और प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए अधिकारी कर्मचारी भी

६९वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं

चंदन सिंह बत्रा
डीएचएफएल प्रमेरिका लाईफ इंश्योरेंस भोपाल

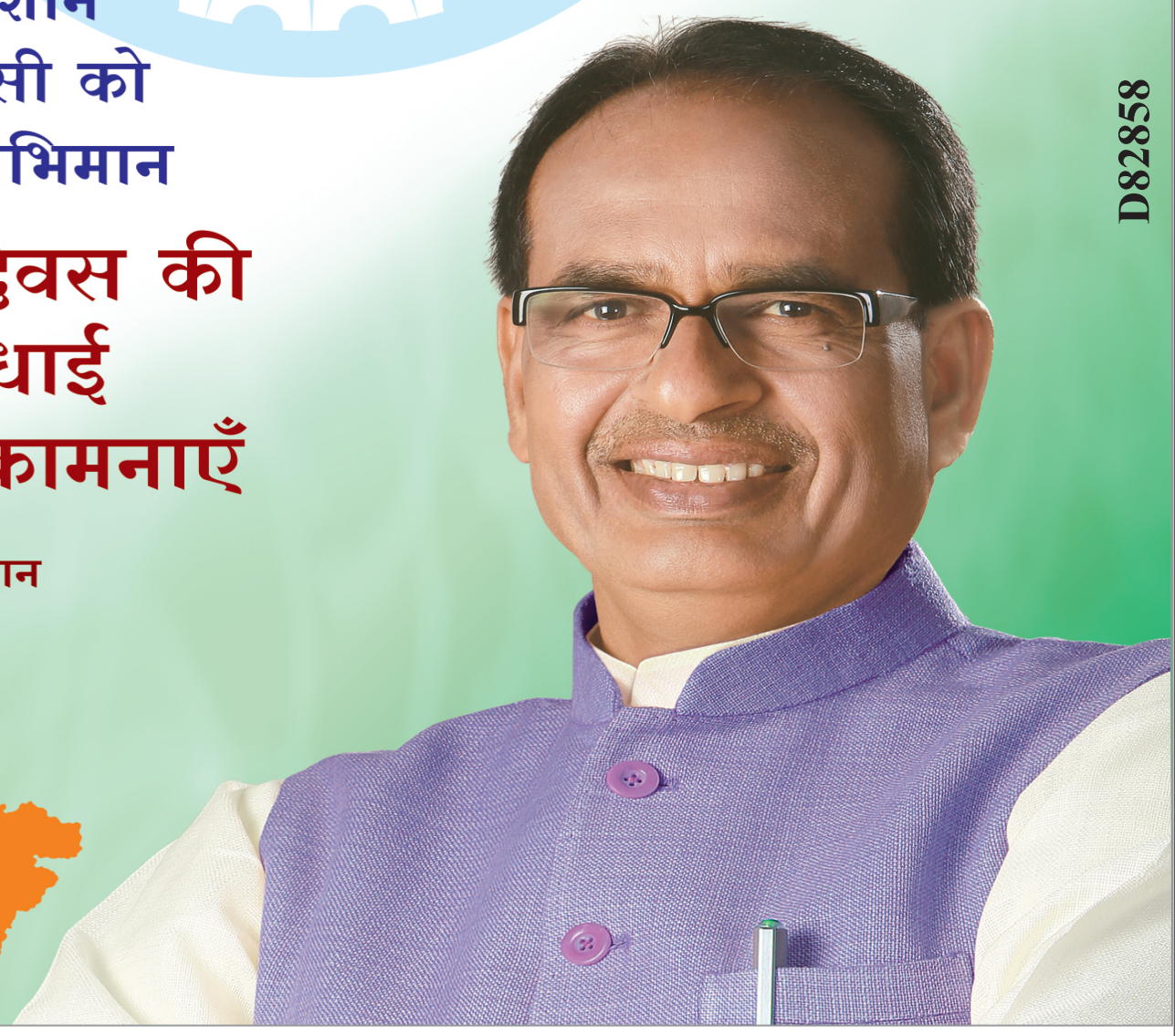

स्वत्वाधिकारी ,मुद्रक,प्रकाशक आलोक सिंघई ने सम्यक प्रिंटर्स से छापा और ऊपरी भूतल-7 अलकनंदा काम्पलेक्स जोन-1,एमपी नगर भोपाल से प्रकाशित किया।
संपादक - आलोकसिंघई फो.2555007,मोबा.-9425376322 न्याय क्षेत्र भोपाल. aloksinghai67@gmail.com सलाहकार संपादक : विपिन शर्मा, स्थानीय संपादक : संजय जैन।